

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित तिथि : 13.12.2012

निर्णय तिथि : 21.10.2013

**रि.या.(सि.) 3704/2012 और
सि.वि.आ.सं.7772, 7774, 8894, 9629 और 10289/2012**

भारत संघ

.....याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री सुधीर वालिया के साथ सुश्री वर्षा
जुनेजा और श्री अखिल सच्चर, अधिवक्तागण

बनाम

निशा प्रिया भाटिया

..... प्रत्यर्थी

द्वारा : सुश्री निशा प्रिया भाटिया, व्यक्तिगत
रूप से प्रत्यर्थी

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. रवींद्र भट

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.वी.ईश्वर

न्यायमूर्ति श्री एस रवींद्र भट

1. इस रिट याचिका में, केंद्र सरकार केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ (इसके बाद "कैट" कहा जाएगा) मू.आ. संख्या 3613/2011 में एक

आदेश द्वारा व्यथित है। कैट ने प्रत्यर्थी/याचिकाकर्ता (इसके बाद "प्रत्यर्थी" या "सुश्री भाटिया" कहा गया है) के आवेदन को अनुमति दी और कथित अनधिकृत अनुपस्थिति के दो चरणों को नियमित करने का निर्देश दिया और केंद्र सरकार को परिणामी लाभों के साथ 19.12.2009 से प्रत्यर्थी की पेंशन को संशोधित करने का भी निर्देश दिया।

2. मामले में निर्णय के लिए आवश्यक तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी कैबिनेट सचिवालय में 1987 बैच के श्रेणी 1 कार्यकारी कैडर [जिसे आर और एडब्ल्यू के नाम से भी जाना जाता है] अधिकारी थी। जिन घटनाओं के कारण 18-12-2009 से उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति हुई, उनकी पुनरावृत्ति की जानी चाहिए। प्रत्यर्थी ने 2007 में किसी समय कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके परिणामस्वरूप दो समितियों का गठन किया गया। यद्यपि इन समितियों की रिपोर्टें इन कार्यवाहियों की प्रत्यक्ष विषय-वस्तु नहीं हैं, फिर भी समिति की रिपोर्टें (दिनांक 19-05-2008 और इसके बाद अन्य समिति की दिनांक 30-09-2008 की रिपोर्ट) ने दर्शाया कि यौन उत्पीड़न के आरोपों को प्रमाणित नहीं किया जा सका। 08.12.2009 को, केंद्र सरकार ने अनुसंधान और विश्लेषण विंग (भर्ती, कैडर और सेवा) नियम, 1975 के नियम 135 (1) (क) के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करके, प्रत्यर्थी को इस आधार पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया कि उसकी पहचान खुफिया अधिकारी के रूप में उजागर हो गई है और इस प्रकार वह संगठन में रोजगार के योग्य

नहीं रह गई है। वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी ने मू.आ. 50/2010 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को चुनौती दी। प्रत्यर्थी दलीलों पर विचार करने के बाद, प्रत्यर्थियों को जारी नोटिस के अनुसरण में, कैट ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के उक्त आदेश को रद्द कर दिया और उन्हें परिणामी राहत देने का निर्देश दिया। बदले में, केंद्र सरकार ने रिट याचिका (सि.) 2735/2010 में इस न्यायालय के सम्मुख कैट के निर्णय पर सवाल उठाया। इस न्यायालय ने दिनांक 03.05.2010 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और इस बीच, कैट के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें प्रत्यर्थी की बहाली का निर्देश दिया गया। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि,

“..... हालांकि, यह नियमों के तहत अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद कानून के अनुसार अपने अनिवार्य सेवानिवृत्ति लाभों का दावा करने के प्रत्यर्थी के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। यदि प्रत्यर्थी अपने पुनः परीक्षण लाभों का दावा करती है, तो उसके द्वारा औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद एक सप्ताह के भीतर उसे जारी किया जाएगा। उसके द्वारा इस तरह के सेवानिवृत्ति लाभों का दावा उसके अधिकारों और विवादों के पूर्वाग्रह के बिना होगा.....”

3. दिनांक 10.05.2010 को केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 ("पेंशन नियम") के नियम 69 के तहत प्रत्यर्थी की अनंतिम पेंशन निर्धारित करने का आदेश जारी किया गया था, जो 28.08.2008 को उसके वेतन पर आधारित था जो 19.12.2009 से प्रभावी हुआ। इस आदेश में कहा

गया है कि अनंतिम पेंशन जारी की जानी चाहिए, दिनांक 19-12-2009 से उसकी अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि तक नियमित कर दी गई है। प्रत्यर्थी ने अनंतिम पेंशन के आदेश को इस हद तक चुनौती दी कि उसने कैट के समक्ष मू.आ. 1665/2010 दाखिल करके अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश की तिथि तक की पर्याप्त अवधि को अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि के रूप में माना। उस कार्यवाही में, प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि 29.08.2008 और 26.11.2009 के बीच कथित अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि के बारे में रि.या. (सि.) 2735/2010 (जिसे आगे "भारत संघ की 2010 याचिका" के रूप में संदर्भित किया गया है) में केंद्र सरकार की दलील उचित नहीं थी। उन्होंने कैट के समक्ष पिछली कार्यवाही का हवाला दिया, जिसमें यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने वाली चल रही कार्यवाही और अधिकरण और उसके परिणामस्वरूप इस न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ आदेशों से निपटा गया था। उन्होंने कैट के समक्ष पिछली कार्यवाही का उल्लेख किया, जिसमें यौन उत्पीड़न के आरोपों और अधिकरण द्वारा किए गए कुछ आदेशों की जांच करने वाली चल रही कार्यवाही से निपटा गया था। प्रत्यर्थी ने बताया कि उन कार्यवाहियों में, यानी मू.प. 2687/2008, केंद्र सरकार ने स्वीकार किया था कि प्रत्यर्थी, 06.04.2009 को कार्यालय का कार्यभार ग्रहण किये। उसने यह भी तर्क दिया कि उसे अपने कार्यालय में जाने से रोका गया था और 29.08.2008 को एसएसबी बटालियन के कमांडर द्वारा दिए गए कथित समर्थन पर भरोसा किया गया था। उक्त आवेदन (मू.आ. 1665/2010) दाखिल करने से पहले, प्रत्यर्थी

ने अपनी अनुपस्थिति की अवधि के नियमितीकरण का दावा करते हुए एक अभ्यावेदन भी दिया था। तथापि, केन्द्र सरकार ने अपने दिनांक 28-05-2010 के आदेश के माध्यम से इसे अस्वीकार कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप उसने उस अस्वीकृति को भी चुनौती दी, मू.आ. 1967/2010 दाखिल करके, मू.आ.1665/2010 में उन लोगों के समान और समान आधार का आग्रह किया।

4. उक्त आवेदनों के लंबित रहने के दौरान, मू.आ. 1665/2010 और मू.आ. 1967/2010, प्रत्यर्थी द्वारा एक अंतरिम/विविध आवेदन (वि.आ.) 2115/2010 दायर किया गया था, जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि समय-समय पर उसे कथित रूप से जारी किए गए सभी संचार प्रस्तुत किए जाएं। प्रत्यर्थी द्वारा एक जवाब दायर किया गया था; केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने दिनांक 29-09-2010 को आवेदन का निपटान कर दिया। इस आदेश के दौरान, कैट ने निम्नलिखित शब्दों में केंद्र सरकार के अधिवक्ता का बयान दर्ज किया:

"XXXX

XXXX

XXXX

2. प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता बार में कहते हैं, प्रत्यर्थीगण के निर्देशों के तहत, कि उपरोक्त चार (दिनांक 01.12.2008, 06.04.2009, 18.02.2010 और 28.05.2010 के पत्र) के अलावा कोई भी पत्र आधिकारिक प्रत्यर्थीगण द्वारा आवेदक को संदर्भ के तहत अवधि के लिए अनुपस्थिति के बारे में विवाद के संदर्भ में संबोधित नहीं किया गया था।

XXXX

XXXX

XXXX

5. प्रत्यर्थी के मूल आवेदन, 1665/2010 और 1967/2010 होने के नाते, यह दावा करते हुए कि अगस्त 2008 और नवंबर 2009 के बीच की अवधि का उपचार अनधिकृत अनुपस्थिति के रूप में उचित नहीं था - 28.04.2011 के सामान्य आदेश द्वारा निपटाया गया था। अधिकरण ने देखा कि उसके आदेश की तिथि तक, प्रत्यर्थी को कोई आरोप पत्र जारी नहीं किया गया था और मामले को खींचा जा रहा था। अधिकरण ने यह भी देखा कि 15.05.2009 के अपने पिछले आदेश में, मू.आ. 2687/2008 में, केंद्र सरकार को प्रत्यर्थी को इयूटी में शामिल होने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था और स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उनके आग्रह को माफ कर दिया जाना चाहिए था। केंद्र सरकार की दलीलों पर भी ध्यान दिया गया। अधिकरण की राय थी कि तथ्यों और आरोपों की विवादित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, पहचान पत्र जारी करने या सही तैनाती आदेश जारी करने में केंद्र सरकार की ओर से देरी या निष्क्रियता के कारण कथित अनुपस्थिति की ऐसी अवधियों को नियमित करने के लिए एक उचित प्रयास किया जाना चाहिए और उसके बाद केंद्र सरकार, इसी अवधि के लिए अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए, प्रत्यर्थी को आरोप पत्र जारी करें और प्रत्यर्थी को अपना बचाव करने का पूरा अवसर दें। इस संबंध में क्रियात्मक निदेश (मू.आ.1665/2010 और मू.आ.1967/2010 में 28.04.2011 को दिए गए) निम्नानुसार थे:

XXXX

XXXX

XXXX

30. उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, दोनों अनिर्णीत आवेदनों का निम्नलिखित निर्देश द्वारा निपटारा किया जा सकता है:-

(i) प्रत्यर्थी पहले कथित अनुपस्थिति की ऐसी अवधि को सही करने का प्रयास करेंगे जो उनकी तरफ से पहचान पत्र जारी करने या सही पोस्टिंग के आदेश देने या किसी न्यायलय के आदेश आदि में विलंब या निष्क्रियता के कारण हुई हो। वे उपस्थिति पर भी विचार करेंगे, जिस पर आवेदक, उसके पीए और उसके साथ संलग्न फील्ड ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ii) उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने के बाद, यदि प्रत्यर्थी अभी भी महसूस करते हैं कि आवेदक कुछ अवधि के लिए अनधिकृत रूप से अनुपस्थित था, तो वे आवेदक को निश्चित आरोप पत्र जारी करेंगे, जिससे उसे अपना बचाव करने का पूरा मौका मिलेगा और फिर कानून के अनुसार अवधि तय होगी।

(iii)

प्रत्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों के खिलाफ आवेदक ने यौन उत्पीड़न या भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज की है, उनमें से किसी को भी जांच अधिकारी या प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त न किया जाए क्योंकि उसे आशंका है कि वे उसके खिलाफ पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं। यह निर्देश इसलिए दिया गया है क्योंकि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए कि न्याय किया गया है।

(iv) यदि प्रत्यर्थी ने जांच शुरू करने का निर्णय लिया है, तो आवेदक द्वारा सहयोग के अधीन इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से 4 महीने के भीतर इसे पूरा किया जाएगा।

(v) हम आवेदक को इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर, प्रत्यर्थियों द्वारा तैयार किए गए चेकों को स्वीकार करने की अनुमति देते हैं, जो निश्चित रूप से उसके अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना होगा।

XXXX

XXXX

XXXX "

6. 29.09.2011 को, सुश्री भाटिया ने मू.आ. 3613/2011 को दायर किया, जिसमें केंद्र सरकार को किसी भी तरह से कार्यवाही करने से रोकने और 29.08.2008 से 26.11.2009 तक कथित अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को मानने के लिए निर्देश देने की मांग की गई और कैट के पिछले आदेश दिनांक 28.04.2011 का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप ड्यूटी से कथित अनधिकृत अनुपस्थिति की उक्त अवधि का नियमितीकरण होना चाहिए, और परिणामी आदेश जारी किये जाने चाहिए। कैट ने नोटिस जारी किया; संघ सरकार ने उपस्थिति दर्ज कराई और दिनांक 14.03.2012 को अपना उत्तर दायर किया। इस उत्तर में केन्द्र सरकार ने बताया कि संयुक्त सचिव द्वारा एक आंतरिक जांच की गई थी, जिन्होंने दिनांक 29-09-2011 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि दिनांक 29-08-2011 से 26-11-2009 तक कथित अनधिकृत अनुपस्थिति की कुल अवधि को ड्यूटी पर माना

जा सकता है। जवाब में यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार के पास दो विकल्प थे, या तो सीसीएस (पेंशन) नियमों के नियम 9 के तहत अनुशासनात्मक प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद छुट्टी देकर अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को नियमित करना, या आरोप पत्र जारी करना। हलफनामे में कहा गया है कि इसमें शामिल मुद्दों की जांच करने के बाद, 27.02.2012 को एक आदेश जारी किया गया था, जिसे सचिव (प्र.) पर उचित कार्रवाई करने के लिए छोड़ दिया गया था। उत्तर में *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नानुसार कहा गया है

XXXX

XXXX

XXXX

5. सचिव (आर), भारत सरकार, पूरे मुद्दे पर विचार करने के बाद और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस मामले में केवल दो विकल्प हैं-

(i) 29-8-2008 से 5-4-2009 और 10-06-2009 से 26-11-2009 (कुल 390 दिन) तक उसकी अनुपस्थिति की अवधि को 226 दिनों की उपार्जित छुट्टी के रूप में और शेष को आधा वेतन अवकाश, यदि कोई हो, के रूप सुश्री भाटिया के खाते में जमा। 6-4-2009 से 9-6-2009 तक की अवधि को इयूटी माना जा सकता है; नहीं तो

(ii) सुश्री भाटिया के विरुद्ध संबंधित पेंशन नियमों के अंतर्गत उनकी अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि के लिए विभागीय जांच शुरू करना ।

6. प्रत्यर्थी के लिए ये सभी सीमित विकल्प उपलब्ध हैं। प्रत्यर्थी नरम रुख अपनाना और याचिकाकर्ता द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय कठिनाइयों के कारण जिसकी दो कॉलेज जाने वाली बेटियां हैं पहले विकल्प के लिए जाना चाहेंगे। प्रत्यर्थी पसंद करेंगे कि सुश्री भाटिया आगे आएँ और उपरोक्त के रूप में अपनी छुट्टी को नियमित करने के लिए सहमत हों। इससे विभाग को पूर्ण पेंशनरी देय राशि जारी करने में मदद मिलेगी जिसे वह राँ अधिकारी (भर्ती,कैंडर और सेवा) नियमावली, 1975 के नियम 135 के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त करने की अधिकारी है। उसकी बकाया पेंशन राशि जिसके लिए वह हकदार बनेगी, वह इस प्रकार है :

राँ अधिकारी (भर्ती,कैंडर और सेवा) नियमावली के नियम 135 के प्रावधान के अनुसार, सुश्री भाटिया को 30.04.2023 को, यानी उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक 75,700/- रुपये का मूल वेतन (एचएजी के बराबर + आईपीएस वेतन नियमों में डीजी को स्वीकार्य 75,500-80,000/- रुपये का स्केल) मिल रहा होगा। इसके आधार पर, वह 19.12.2009 से 37,850/- रुपये (75,700 रुपये का 50%) की मूल पेंशन और उस पर महंगाई राहत (डीआर) पाने की हकदार हैं। वर्तमान में, उसके द्वारा स्वीकृत किया गया है और उसके द्वारा स्वीकृत 27,770/- रुपये प्लस डीआर की अनंतिम पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। यह स्थिति तब तक जारी रहेगी जब तक अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि तय नहीं हो जाती।

7. हालांकि, अगर यह याचिकाकर्ता को स्वीकार्य नहीं है और वह ड्यूटी से अपनी अनुपस्थिति को नियमित करने से

इनकार करती है, तो प्रत्यर्थी के पास याचिकाकर्ता के खिलाफ प्र.सा.(प्रतिरक्षा साक्ष्य) के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। यदि कोई प्र.सा.(प्रतिरक्षा साक्ष्य) रखा जाता है जिसके लिए ऐसा करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है, तो यह आवेदक को केन्द्रीय नागरिक सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 9 के तहत आयोजित की जाने वाली लंबी विभागीय कार्यवाही में खींच लेगा, जिसे पूरा होने में समय लग सकता है। आवेदक को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता रहेगा क्योंकि उसे विभागीय जांच को अंतिम रूप दिए जाने तक अंतिम पेंशन नहीं मिलेगी।

8. यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि यह निर्णय इस माननीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 28.04.2011 के आदेश की भावना को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

XXXX

XXXX

XXXX "

7. सुश्री भाटिया ने एक विविध आवेदन (एम.ए.) दायर किया था, जिसमें उनके मूल आवेदन की शीघ्र सुनवाई और निपटान के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। जवाब में, भारत संघ ने कुछ आरोपों से इनकार करने और यह रेखांकित करने के बाद कि प्रत्यर्थी के आवेदनों में न्यायाधीशों के खिलाफ अनुचित आरोप हैं, इस प्रकार कहा:

XXXX

XXXX

XXXX

6..... हालांकि, माननीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 28.04.2011 के आदेश की भावना को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी एक बार फिर 14.03.2012 के उत्तर के पैरा 5 में किए गए कथनों को दोहराता है। इस मामले पर आगे विचार करने पर, यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 14.03.2012 के उत्तर में पहले किए गए प्रस्ताव के आगे, प्रत्यर्थी अपनी अनुपस्थिति की अवधि को "चाइल्ड केयर लीव" के रूप में मानने के लिए तैयार है। उस स्थिति में, आवेदक (सुश्री निशा प्रिया भाटिया) को कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा। जैसा कि पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है, उसकी अनुपस्थिति की कुल अवधि - 29.08.2008 से 26.11.2009 है। संयुक्त सचिव द्वारा की गई आंतरिक जांच के अनुसार, उपस्थिति रजिस्टर की प्रति पर विचार करने के बाद, 07.04.2009 से 09.06.2009 (63 दिन) की अवधि को "इयूटी पर" माना जा सकता है, जिससे उसे संदेह का लाभ मिलता है। जहां तक दिनांक 29-08-2008 से 05-04-2009 तथा 10-06-2009 से 26-11-2009 (390 दिन) तक की शेष अवधि का संबंध है, को बाल देखभाल अवकाश/उपार्जित अवकाश माना जा सकता है।

7. यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि आवेदक (सुश्री निशा प्रिया भाटिया) को अन्य सभी लाभों के साथ पूरी अवधि अर्थात् 29.08.2008 से 26.11.2009 के लिए पूरे वेतन का भुगतान किया गया है, जिसकी वह हकदार थी।

XXXX

XXXX

XXXX

आक्षेपित आदेश

8. कैट ने अपने आक्षेपित आदेश द्वारा ओए 3613/2011 को अनुमति दी 11.05.2012. इस आदेश के दौरान, कैट ने नोट किया कि इस कार्यवाही का दायरा रॉ में यौन उत्पीड़न की सत्यता या प्रत्यर्थी के खिलाफ दर्ज कुछ आपराधिक मामलों की शुद्धता तय करना नहीं था। इसने 29.08.2008 से 26.11.2009 की अवधि के लिए अनधिकृत अनुपस्थिति के मुद्दे पर विचार करने के लिए 07.04.2009 से 09.06.2009 की अवधि को घटाकर अपने अधिकार क्षेत्र के दायरे को निर्धारित किया है। न्यायाधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ देखा कि उसके पिछले आदेशों में देखा गया है कि:

"8... न्यायाधिकरण ने पाया कि कुछ अवधियाँ, जो विवादित थीं, प्रत्यर्थियों द्वारा स्वयं ही नियमित की जा सकती थीं, तथा प्रत्यर्थियों ने स्वीकार किया था कि आवेदक ने 28.05.2008 को औपचारिक रूप से नए पहचान पत्र के लिए आवेदन किया था, जो 10.02.2009 को जारी किया गया, अर्थात् साढ़े नौ महीने से अधिक की अवधि के बाद, तथा यदि प्रत्यर्थियों ने पहचान पत्र तैयार करने में इतना समय लिया था, तथा आवेदक को पहचान पत्र के अभाव में कार्यालय में आने की अनुमति नहीं दी गई थी, तो उक्त अवधि को आवेदक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है..."

9. हालांकि, कैट ने माना कि प्रत्यर्थियों को अनुपस्थिति की ऐसी अवधि को नियमित करने का प्रयास करना आवश्यक था, जो पहचान पत्र जारी करने और

उपस्थिति रजिस्टर जारी करने में उनकी ओर से देरी या निष्क्रियता के कारण हो सकती थी। यह माना गया कि 10.02.2009 तक यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि प्रत्यर्थी अनधिकृत अनुपस्थिति पर था और वैध पहचान पत्र के अभाव में कार्यालय में उपस्थित नहीं होने के लिए उसके पास वैध कारण थे। इस प्रकार इसने प्रत्यर्थी के तर्कों को स्वीकार कर लिया कि उसे कर्तव्यों में शामिल होने से रोका जा रहा है। न्यायाधिकरण ने यह भी पाया कि, "आवेदक ने यह भी तर्क दिया कि, "अनधिकृत अनुपस्थिति की इस अवधि के दौरान उसे नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया गया था और उक्त अवधि के दौरान कभी भी उसे यह बताने के लिए नहीं कहा गया था कि वह किन परिस्थितियों में अनुपस्थित रही थी..... यह दोहराने के बाद कि यौन उत्पीड़न के संबंध में आरोपों की सत्यता की जांच नहीं की जानी चाहिए, न्यायाधिकरण ने पाया कि पहचान पत्र तैयार करने में लगभग साढ़े नौ महीने लग गए थे; और यह कि एक चिकित्सक से यह कहते हुए एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था कि वह एक मनोरोगी थी। इन तथ्यों को केन्द्र सरकार द्वारा विवादित नहीं किया गया था। इन और अन्य तथ्यों पर प्रतिकूल टिप्पणी करने से परहेज करते हुए भी, न्यायाधिकरण ने यह मानने के लिए विवश महसूस किया कि प्रत्यर्थी के साथ उदासीनता से व्यवहार किया गया था। यह भी देखा गया कि कोई जांच शुरू नहीं की गई थी और इस मुद्दे पर निर्णय लेने में केंद्र सरकार की ओर से लंबे समय तक देरी के मद्देनजर, इस तरह की अवधि को अनधिकृत अनुपस्थिति

पर खर्च करने के रूप में मानना उचित नहीं था, इस प्रकार प्रत्यर्थी को पूर्ण पेंशन के लिए वंचित कर दिया गया था। इन निष्कर्षों के प्रकाश में, न्यायाधिकरण ने मू.आ. 3613/2011 की अनुमति दी, और निर्देश दिया कि दिनांक 29-08-2008 से 05-04-2009 और 10-06-2009 से 26-11-2009 तक कथित अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को नियमित किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार को भी कोई जांच न करने का निदेश दिया गया था और प्रत्यर्थी की मूल पेंशन को संशोधित करने का निर्देश दिया गया था और 19-12-2009 से स्वीकार्य महंगाई राहत के साथ 37,850/- रुपए निर्धारित किया गया था।

केंद्र सरकार की दलीलें

10. संघ ने अपनी दलीलों और विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री पीपी मल्होत्रा की प्रस्तुतियों में तर्क दिया है कि आक्षेपित आदेश उन प्राप्तियों में त्रुटिपूर्ण है कि प्रत्यर्थी अपने इयूटी नहीं कर सकी, क्योंकि उसे नया पहचान पत्र जारी नहीं किया गया था। यह तर्क दिया गया कि ये निष्कर्ष रिकॉर्ड के पूरी तरह से विपरीत हैं, क्योंकि संगठन के किसी भी अधिकारी को कभी भी इस आधार पर कार्यालय में प्रवेश करने से नहीं रोका गया था कि उसके पहचान पत्र का नवीनीकरण नहीं किया गया है। सरकार ने परिपत्र जारी किए थे जिनमें नवीकरण की अंतिम तारीख को समय-समय पर बढ़ाया गया था। इन अभिलेखों को पिछली कार्यवाही [मू.आ.1665/2010 एवं 1967/2010] में न्यायाधिकरण के समक्ष पेश किया गया था, जिसने विभाग को दिनांक 28.04.2011 के

आदेश द्वारा तथ्य के इन विवादित प्रश्नों के संबंध में जांच करने का निर्देश दिया था।

11. यह तर्क दिया गया था कि भले ही न्यायाधिकरण ने पाया कि यह यौन उत्पीड़न से संबंधित आरोपों से संबंधित मुद्दों से संबंधित तथ्यों से संबंधित नहीं था और केवल यह तय करने जा रहा था कि प्रत्यर्थी के खिलाफ कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के बारे में विभागीय जांच की जानी चाहिए या नहीं, फिर भी, अपने आक्षेपित आदेश में इन सभी मुद्दों पर प्रतिकूल निष्कर्ष वापस करने के लिए आगे बढ़े, बिना किसी सामग्री के इसका समर्थन करने के लिए और आदेश में किसी भी रिकॉर्ड के लिए कॉल किए बिना इन आरोपों की सत्यता या अन्यथा तय करने के लिए।

12. यह तर्क दिया गया था कि न्यायाधिकरण ने इस बात की अनदेखी की कि भारत संघ ने आदेश की भावना को देखते हुए इस मामले में उदार दृष्टिकोण अपनाया था (ख) सरकार ने दिनांक 14032012 और 30042012 के अपने शपथपत्रों में एक प्रस्ताव रखा था जिसे प्रत्यर्थी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थी की अनधिकृत अनुपस्थिति के प्रश्न के संबंध में विभाग द्वारा उठाए गए उदार रुख पर गलती से प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया। यह तर्क दिया गया है कि आक्षेपित निर्णय में इस तरह की टिप्पणियां न्यायाधिकरण की एक अन्य पीठ द्वारा दिनांक 28.04.2011 के आदेश के पैरा 30 में जारी किए गए निर्देशों के विपरीत थीं। इस बात पर जोर

दिया गया कि विभाग ने एक उदार दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया था और पहला विकल्प दिया था, यानी अनधिकृत अनुपस्थिति की शेष अवधि को नियमित करने के लिए, बशर्ते प्रत्यर्थी ने इस संबंध में एक औपचारिक आवेदन करके इसे स्वीकार कर लिया। यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि न्यायाधिकरण के समक्ष संघ के हलफनामे में कहा गया था, अपने पहले के आदेश में, कि यदि प्रत्यर्थी ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, तो विभाग के पास कोई अन्य विकल्प नहीं होगा, लेकिन प्रत्यर्थी के खिलाफ विभागीय जांच करनी होगी। विद्वान एएसजी ने रिट याचिका में आग्रह किए गए निम्नलिखित आधार पर भरोसा किया:

"यहां यह प्रस्तुत करना भी महत्वपूर्ण है, कि विभाग ने 30.04.2012 को प्रत्यर्थी द्वारा ओए संख्या 3613/2011 में दायर आवेदन (वि.आ.संख्या 919/2012) के जवाब में एक और हलफनामा दायर किया, जिसमें प्रत्यर्थी को एक और विकल्प दिया गया था कि विभाग ने अपने हलफनामे दिनांक 14.03.2012 में किए गए अपने पहले के प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए, उसकी अनुपस्थिति की अवधि को "चाइल्ड केयर लीव" के रूप में मानने के लिए तैयार है, ताकि प्रत्यर्थी को कोई वित्तीय नुकसान न हो। तथापि, यह प्रस्ताव प्रत्यर्थी द्वारा विभाग को औपचारिक आवेदन करने के अधीन था. यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि सुनवाई के दौरान, माननीय न्यायाधिकरण ने विशेष रूप से विभाग के अधिकारी से पूछा था, जो अदालत में मौजूद थे, क्या विभाग इस बात से सहमत था कि कोई विभागीय जांच नहीं की जाएगी, यदि प्रत्यर्थी ने उसकी अनुपस्थिति की अवधि को नियमित करने के लिए आवेदन किया है? विभाग से

निर्देश प्राप्त करने के बाद, माननीय पीठ को सूचित किया गया कि विभाग मामले को समाप्त कर देगा और कोई विभागीय जांच शुरू नहीं की जाएगी, यदि प्रत्यर्थी द्वारा ऐसा आवेदन दिया जाता है तब।

13. विद्वान अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी की अनधिकृत अनुपस्थिति के बारे में प्रश्न केवल तथ्यों के विवादित प्रश्न होने के मद्देनजर नियमित विभागीय जांच में तय किया जा सकता है। अधिकरण इस मामले की जांच नहीं कर सकता था और शपथपत्रों के आधार पर तथ्यों के जटिल प्रश्नों का निर्णय नहीं कर सकता था और विभाग को इन मुद्दों पर प्रासंगिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिए बिना निर्णय नहीं दे सकता था।

14. अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि विवादित आदेश इसलिए भी अस्वीकार्य है क्योंकि इसमें इस बात की अनदेखी की गई है कि प्रत्यर्थी द्वारा केंद्र सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद, केंद्र सरकार ने अनुरोध किया था कि उसे 28.04.2011 के आदेश के पैरा 30(ii) में निहित निर्देशों के अनुसार विभागीय जांच करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को नियमित करने तथा साथ ही किसी भी प्रकार की जांच से परहेज करने के लिए निर्देश जारी करके न्यायाधिकरण ने ऐसे निष्कर्षों पर आधारित आदेश दिया था जो उसके पिछले निर्देशों के विपरीत थे तथा अपुष्ट मान्यताओं पर आधारित थे। अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि

को नियमित करने तथा साथ ही किसी भी प्रकार की जांच से परहेज करने के लिए विवादित निर्देश जारी करके न्यायाधिकरण ने ऐसे निष्कर्षों के आधार पर आदेश दिया था जो उसके पिछले निर्देशों के विपरीत थे तथा अपुष्ट मान्यताओं पर आधारित थे। यह तर्क दिया गया कि न्यायाधिकरण के पिछले आदेश और आरोपित आदेश को संयुक्त रूप से पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चला है कि पहले के आदेश में कहीं भी तथ्यों का निष्कर्ष नहीं दिया गया था, जो बाद के आदेश की अंतर्निहित धारणाओं के विपरीत था। पेंशन नियमों के नियम 9 के अनुसार, न्यायालय केन्द्र सरकार को अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने तथा जांच करने के अपने विवेक प्रयोग को रोक नहीं सकता। यह केन्द्र सरकार को पेंशन नियमावली के नियम 9 के अनुसार अपनी सांविधिक शक्तियों का प्रयोग करने और जांच कराने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने से भी रोक नहीं सकता था।

15. केंद्र सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि न्यायाधिकरण ने आवश्यक तथ्यों की अनदेखी करने में गलती की है, जो मू.आ. संख्या 1665/2010 और 1967/2010 में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत रिकॉर्ड से स्पष्ट थे, अर्थात्:

(क) सुश्री भाटिया के पहचान-पत्र की अवधि 31-08-2008 को समाप्त होनी थी। उसने 21.08.2008 को अपने पहचान पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया और उसका आवेदन 25.08.2008 को कार्यालय में प्राप्त हुआ;

(ख) निर्देशानुसार, पहचान पत्र की नई श्रृंखला जारी करने के लिए सभी अधिकारियों को मुख्यालय में फोटो खींचना पड़ा। इसी पत्र में उन्हें मौजूदा पहचान पत्र धारकों को 30.11.2008 तक अपने पुराने पहचान पत्र का उपयोग करने की अनुमति देने के बारे में नवीनतम निर्देशों के बारे में भी सूचित किया गया था;

(ग) सुश्री भाटिया नए पहचान पत्र जारी करने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आगे नहीं आईं;

(घ) 31-08-2008 के नवीकरण की समय-सीमा 30-11-2008 तक बढ़ा दी गई थी।

परिपत्र दिनांक 21.08.2008 - सभी अधिकारियों को कार्यालय में प्रवेश और निकास के लिए अपने पुराने पहचान पत्र का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी ;

(ड) नवीकरण की समय-सीमा को 31-12-2008 तक और बढ़ा दिया गया था।

परिपत्र दिनांक 26.11.2008 - सभी अधिकारियों को कार्यालय में प्रवेश और निकास के लिए अपने पुराने पहचान पत्र का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी।

कार्ड;

(च) नए पहचान पत्र नहीं ले पाने वाले सभी कर्मचारियों को कार्यालय में प्रवेश और निकास के उद्देश्य से 'दैनिक पास' प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। नए पहचान पत्र जारी न होने के कारण किसी भी अधिकारी को प्रवेश से मना नहीं किया गया।

(छ) सुश्री भाटिया द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें 04-02-2009 को एक अस्थायी पहचान पत्र जारी किया गया था;

(ज) 10.02.2009 को उन्हें एक स्थायी पहचान पत्र जारी किया गया था;

16. यह तर्क दिया जाता है कि किसी भी अधिकारी को नए पहचान पत्र जारी न करने के कारण कार्यालय में प्रवेश करने से रोका या वंचित नहीं किया गया था जैसा कि ऊपर बताया गया है। सुरक्षा अधिकारी 31-12-2008 के बाद से उन सभी लोगों को दैनिक पास जारी कर रहे थे जिनके नए पहचान पत्र अधूरी औपचारिकताओं के कारण तैयार नहीं थे। इसलिए यह तर्क दिया गया कि सुश्री भाटिया ने नए पहचान पत्र जारी करने की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया, भले ही समय-समय पर अवधि बढ़ाई गई थी। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि सुश्री भाटिया ने भी 31.12.2008 के बाद अन्य अधिकारियों की तरह दैनिक पास के लिए आवेदन नहीं किया। यह कहा गया है कि मू.आ. सं. 1665/2010 & 1967/2010 की सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार ने दिनांक 21.08.2008 और 26.11.2008 के परिपत्रों के साथ दिनांक 15.09.2008 का पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें यह प्रदर्शित किया गया था कि प्रत्यर्थी के कथन

तथ्यात्मक रूप से गलत थे। उन तथ्यों को प्रत्यर्थी द्वारा विवादित किया गया था और इसलिए न्यायाधिकरण ने 28.04.2011 के पिछले आदेश के पैरा 29-30 में केंद्र सरकार को पहचान पत्र जारी करने के मुद्दे को हल करने का निर्देश दिया, सबसे पहले अनुपस्थिति की ऐसी अवधि को नियमित करने का प्रयास करके, जो पहचान पत्र जारी करने में देरी या निष्क्रियता के कारण हुई।

17. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण , मान्यताओं पर कार्यवाही करने के अलावा, केंद्र सरकार को एक आभासी निवारक आदेश द्वारा पेंशन नियमों के नियम 9 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से नहीं रोक सकता था, जैसा कि यह था। प्रावधान के तहत शक्ति सार्वजनिक हित में थी, अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए, और कोई न्यायाधिकरण या न्यायालय इस मामले में अपने विवेक को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती थी।

प्रत्यर्थी की दलीलें

18. प्रत्यर्थी , सुश्री भाटिया का तर्क है कि 5 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद केंद्र सरकार ने कैट द्वारा जारी निर्देशों की अनदेखी की; इसने न तो उनकी कथित अनधिकृत अनुपस्थिति (29.08.08 से 26.11.09 तक) की अवधि को नियमित किया, क्या कानून के अनुसार मामले पर निर्णय करने के लिए उन्हें कोई आरोप पत्र जारी किया। केंद्र सरकार को इस मामले को अंतहीन

रूप से दबाए रखने और उसे (प्रत्यर्थी) परेशान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

19. 26.10.07 को यह तर्क दिया जाता है कि, प्रत्यर्थी ने राँ में महिला कर्मचारियों के यौन शोषण और सचिव यानी श्री अशोक चतुर्वेदी की इसके प्रति उदासीनता और भागीदारी के के बारे में सक्षम प्राधिकारी से शिकायत की। इसके बाद उसकी परेशानी शुरू हुई; शिकायत के एक माह के भीतर और उसकी पीठ पीछे, स्टाफ अधिकारी से लेकर सचिव तक के हाथ में दिनांक 26-11-2007 को एम्स अस्पताल के एक डाक्टर (डा रजत राय) द्वारा भेजा गया एक पत्र गया जिसमें "आवेदक को एक मनोरोगी बताया गया। तत्पश्चात् श्री अशोक चतुर्वेदी द्वारा यह दिखाने के लिए प्रचारित किया गया कि सुश्री भाटिया मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति थीं और साथ ही अवज्ञा की भी दोषी थीं। यह तर्क दिया गया था कि जहां भी प्रत्यर्थी अपनी शिकायतों के साथ - पीएमओ, राष्ट्रीय महिला आयोग, एनएचआरसी, या पुलिस के पास गई - उसे इस आरोप के साथ दूर कर दिया गया कि उसने श्री अशोक चतुर्वेदी के खिलाफ शिकायत की थी क्योंकि वह मानसिक रूप से अस्थिर थी। आरोप है कि उसके खिलाफ निगरानी रखी गई और उसके फोन टैप किए गए। वह दिनांक 20.04.2010 के एक पत्र का हवाला देती हैं जो भारतीय सेना के आरटीआई प्रकोष्ठ द्वारा उनके द्वारा दायर आरटीआई आवेदन के जवाब में लिखा गया था, जिसमें निम्नलिखित बातें कही गई थीं:

राँ के संयुक्त सचिव एनके शर्मा के अनुसार, श्रीमती निशा प्रिया भाटिया के खिलाफ सहकर्मियों को परेशान करने, सरकारी संपत्ति को नष्ट करने और काम में बाधा डालने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है। उनकी आवाजाही पर नजर रखने के लिए उनके आवास के आसपास सीसीटीवी लगाए गए हैं क्योंकि उन्होंने पूर्व में प्रधानमंत्री कार्यालय से आत्महत्या करने की कोशिश की थी।

20. सुश्री भाटिया ने कहा कि उनके वरिष्ठों द्वारा उन्हें काम से बाहर रखने के प्रयास नवंबर, 2007 में शुरू हुए - 26.10.07 को उनकी शिकायत के एक महीने से भी कम समय के भीतर श्री अशोक चतुर्वेदी ने दिनांक 08.11.07 को एक आदेश द्वारा उन्हें निदेशक (प्रशिक्षण) के रूप में और एक अन्य अधिकारी, श्री एसएस महापात्र, तत्कालीन निदेशक (प्रशिक्षण) के रूप में निदेशक (जनसंपर्क) मुख्यालय के रूप में तैनात किया। तथापि, एक सप्ताह बाद दिनांक 16-11-07 के एक अन्य आदेश द्वारा निदेशक (जनसंपर्क) के रूप में श्री एसएस महापात्र की तैनाती रद्द कर दी गई थी। इसका अर्थ है कि निदेशक (प्रशिक्षण) के एक बार स्वीकृत पद पर दो अधिकारियों को तैनात किया गया था और चूंकि श्री महापात्र वर्तमान निदेशक (प्रशिक्षण) थे, इसलिए प्रत्यर्थी को बिना किसी कार्य प्रभार के छोड़ दिया गया था। राँ में निदेशक (प्रशिक्षण) का केवल एक स्वीकृत पद है; इसके लिए प्रत्यर्थी ने लेखा अधिकारी (बी एंड एफ) द्वारा दिनांक 08.04.08 को की गई नोटिंग का सहारा लिया। प्रत्यर्थी को, जिस संस्थान की वह प्रमुख थी, वहां शौचालय के बगल में बैठने के लिए एक जर्जर कक्ष दिया गया था। उसे पहले छुट्टी पर जाने के लिए मजबूर किया गया और

फिर उसे संघर्ष करने, शिकायत करने और निदेशक (प्रशिक्षण) का कार्यभार पुनः प्राप्त करने के लिए पीएमओ में प्रतिनिधित्व करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

21. सुश्री भाटिया ने कहा है कि तैनाती आदेशों के कारण उन पर लगाए गए संयम को समिति द्वारा विधिवत नोट किया गया था जिसने श्री अशोक चतुर्वेदी के खिलाफ उनकी शिकायत की जांच की थी। समिति ने दिनांक 23-01-2009 को अपना विचार-विमर्श पूरा कर लिया। हालांकि, राष्ट्रपति भवन के कैबिनेट सचिवालय- जिसके तत्वावधान में यह जांच की गई थी- ने उन्हें अपनी रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध नहीं कराई। इसने उसे न्यायालय के मामले दर्ज करने के लिए मजबूर किया। इनकी परिणति सर्वोच्च न्यायालय में एक अवमानना याचिका यानी विशेष अनुमति याचिका (सि.) संख्या 1257/2010 के रूप में हुई। विशेष अनुमति याचिका में दिनांक 04.07.11 के अंतरिम आदेश के आंशिक अनुपालन में, कैबिनेट सचिवालय ने सभी गवाहों के नाम हटाने के बाद उनकी जांच रिपोर्ट के 18 पृष्ठों को सौंप दिया। प्रत्यर्थी रिपोर्ट के निम्नलिखित उद्धरण (पृष्ठ 64) पर निर्भर करता है कि:

"सुश्री निशा प्रिया भाटिया को आदेश संख्या 4/एसपीएस/2007 (2) 8657 दिनांक 08.11.2007 के तहत निदेशक (प्रशिक्षण) के रूप में वापस गुड़गांव में तैनात किया गया था। इस आदेश से यह भी संकेत मिलता है कि गुड़गांव दिल्ली की तरह कार्यभार संभालेगा। आदेश संख्या 4/एसपीएस/2007 (2) - 864 दिनांक 16 नवंबर

2007 द्वारा संशोधित किया गया था, इसलिए प्रभारों का आदान-प्रदान, जैसा कि पहले आदेश दिनांक 8.11.2007 में परिकल्पित किया गया था, प्रभावी नहीं था।

इसलिए, जब सुश्री निशा प्रिया भाटिया को प्रशिक्षण संस्थान में वापस तैनात किया गया था, तो वह निदेशक (प्रशिक्षण) के रूप में परिवर्तन करने में सक्षम नहीं थीं, जैसा कि दिनांक 08.11.2007 के आदेश में निर्देशित किया गया था, जारी रहा क्योंकि इसलिए वह वहां निदेशक स्तर की दूसरी अधिकारी बन गईं। स्थिति निश्चित रूप से उनके लिए अजीब रही होगी क्योंकि उसके पास अब वह शक्ति और लाभ नहीं था जो निदेशक (टीआरजी) के रूप में उसके पहले कार्यकाल में उनके पास था। वह 21 नवंबर 2007 को छुट्टी पर चली गईं, यह स्थिति तब ठीक हुई जब उन्हें प्रशिक्षण संस्थान से बाहर भेज दिया गया और 17 दिसंबर 2007 को गुड़गांव में निदेशक (प्रशिक्षण) के पद पर बदलाव किया गया। पूरी स्थिति ने उस समय कार्यस्थल पर एक दुर्भावनापूर्ण वातावरण पैदा कर दिया गया था जब श्री अशोक चतुर्वेदी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत को विभागीय शिकायत समिति को भी नहीं भेजा गया था। प्रत्यर्थी को इन पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए था और सुश्री निशा प्रिया भाटिया को काम करने के लिए एक उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए था। प्रत्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि 8 नवंबर 2007 के आदेश का अनुपालन किया गया था और सुश्री निशा प्रिया भाटिया को इस आदेश के अनुसार निदेशक (प्रशिक्षण) के रूप में प्रशिक्षण संस्थान का प्रभार दिया गया था।

यह प्रस्तुत किया गया है कि श्री अशोक चतुर्वेदी के खिलाफ प्रत्यर्थी की शिकायत के बारे में आरोप क्योंकि वह मानसिक रूप से अस्थिर थी,

प्रमुख समाचार पत्रों में दिखाई देने लगे थे। उसके वरिष्ठों ने भी गद्दी कारणों को लेकर उसके खिलाफ पूछताछ शुरू करने का प्रयास किया। 23-07-08 की देर शाम उनके कार्यालय पर छापा मारा गया। जांच रिपोर्ट में इस घटना को निम्नलिखित शब्दों में नोट किया गया है:

"शिकायत

1. "23 जुलाई, 2008 की शाम को, शिकायतकर्ता के कार्यालय परिसर पर नई दिल्ली से विभाग के सुरक्षा अधिकारियों द्वारा छापा मारा गया था, 23 जुलाई का छापा विभाग द्वारा शिकायतकर्ता को सूचित करने और उसे एक संस्थान में उसके सहयोगियों के जिसकी वह तीन साल से प्रमुख थी उनके सामने अपमानित करने का एक खुला प्रयास था। 25 अगस्त 2008 का जापन शिकायतकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री को एसीपीआर (प्रधानमंत्री आवास पर नियुक्ति प्रकोष्ठ) के माध्यम से की गई शिकायत के बाद की छापेमारी को छुपाने के लिए किया गया था।

निष्कर्ष

इस घटना को सुरक्षा जांच के रूप में इंगित किया गया था न कि छापेमारी के रूप में। हालांकि, यह तथ्य कि जांच के बारे में जानकारी संस्थान के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध थी, न कि निदेशक (प्रशिक्षण) के लिए, शायद ऐसा करने के लिए कहा गया था। "

22. प्रत्यर्थी ने छापे को अपने खिलाफ निर्देशित आपराधिक धमकी का कार्य बताया। वह लगातार चिंतित रहने लगी और उसका उत्पीड़न बढ़ गया। 29-08-08 को, वह हमेशा की तरह गुड़गांव में अपने कार्यालय गई; दोपहर में

दोपहर के भोजन के दौरान, श्री अशोक चतुर्वेदी द्वारा उनकी सरकारी कार और ड्राइवर को अचानक वापस बुलालिया गया। चालक ने उसे सूचित किया कि उसे वहां छोड़ कर और फिर वाहन के साथ मुख्यालय में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। उसने गुड़गांव में विभाग के प्रशिक्षण संस्थान में अपने कार्यालय लौटने के लिए एक टैक्सी किराए पर ली। वहां, काउंटर इंटेलिजेंस अधिकारी और एसएसबी प्लाटून के जवान इस परिसर की सुरक्षा करते हैं, उसे अपने कार्यालय परिसर में प्रवेश करने से रोकने के लिए बल प्रयोग करते हैं। उसने पाया कि काउंटर इंटेलिजेंस अधिकारी उसके कार्यालय के भीतर थे और उसके सभी समान को अपने नियंत्रण में रखे हुए थे। ये आपराधिक अतिचार और गलत तरीके से रोक लगाने के कृत्य थे। अनुलग्नक ए/10 (पृष्ठ 69) पर जांच रिपोर्ट में निम्नलिखित शब्दों में उनकी आधिकारिक स्थिति के विषय पर ध्यान दिया गया है।

"शिकायत

2. शिकायत समिति ने माना कि सुश्री भाटिया की आधिकारिक स्थिति के संबंध में कई प्रश्न थे। यह मुद्दा तब उठाया गया जब श्री अशोक चतुर्वेदी 6 दिसंबर, 2008 को समिति के समक्ष उपस्थित हुए।

निष्कर्ष

यह पूछे जाने पर कि क्या अगस्त 2008 में सुश्री निशा प्रिया भाटिया को अनिवार्य प्रतीक्षा पर रखा गया था, श्री अशोक चतुर्वेदी ने शिकायत समिति को बताया कि अनिवार्य प्रतीक्षा की

प्रणाली राँ के प्रचलन में नहीं है। सुश्री निशा प्रिया भाटिया की अतिरिक्त सचिव (प्रशिक्षण) से संबद्ध निदेशक के रूप में नियुक्ति विभाग में किसी भी अन्य सामान्य नियुक्ति की तरह ही थी। वह सभी सामान्य सुविधाओं, कमरे, स्टाफ आदि की हकदार थी, जो उन्हें दी गई थी। यह पूरी तरह से अलग मामला है कि उन्होंने पद से दूर रहने का फैसला कर उनका लाभ नहीं उठाया।

दिनांक 06.12.2008 को श्री अशोक चतुर्वेदी के साथ चर्चा के पश्चात समिति को मंत्रिमंडल सचिवालय के दिनांक 18.12.2008 के पत्र संख्या 501/28/2/2008-सीए.वी के माध्यम से ज्ञात हुआ कि सुश्री निशा प्रिया भाटिया को दिनांक 1-12-2008 को आदेश संख्या 1/63/2007-टी.एल. 5594 जारी किया गया था, जो 7-12-2008 को उन्हें हाथों-हाथ दिया गया था। उनके दिनांक 8-12-2008 के पत्र के अनुसार, सुश्री भाटिया ने संकेत दिया है कि संदर्भित पत्र में 29-08-2008 से इयूटी से उनकी अनुपस्थिति का आरोप लगाया गया है जो कि अनधिकृत है।

यह स्पष्ट नहीं है कि विभाग ने सुश्री निशा प्रिया भाटिया से इयूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण मांगने में 3 महीने से अधिक का समय क्यों लिया।"

सुश्री भाटिया प्रस्तुत करती हैं कि यह निष्कर्ष इस बात का प्रमाण है कि सरकार ने 1 दिसंबर 2008 को उनकी अनुपस्थिति के संबंध में केवल उसके बाद ही इयूटी से अनुपस्थिति के संबंध में पत्र जारी किया था। जांच समिति द्वारा इस विषय पर पूछताछ की गई थी। वह यह भी कहती है कि किसी भी राज्य एजेंसी ने किसी भी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया, और धमकी और अतिचार के कृत्यों के बारे में सचिव और अतिरिक्त सचिव को 30 अगस्त,

2008 के टेलीग्राम की प्रतियों पर भरोसा किया; वह प्रशिक्षण परिसर की सुरक्षा में तैनात एसएसबी प्लाटून के कमांडर द्वारा जारी 31.08.2008 के पत्र पर भी भरोसा करती हैं कि उनके कार्यालय को काउंटर इंटेलिजेंस अधिकारियों द्वारा बंद कर दिया गया था। वह धमकी के ऐसे कृत्यों के खिलाफ पुलिस को 11.09.2008 को की गई शिकायत और 2010 के सीपीआईओ, दिल्ली पुलिस को एक आरटीआई आवेदन पर भी भरोसा करती है, जिसमें कार्रवाई की गई जानकारी मांगी गई थी।

23. सुश्री भाटिया का तर्क है कि उनकी अनुपस्थिति पर केंद्र सरकार के आरोप निराधार थे, जो इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि अनुपस्थिति की अवधि के बारे में अनिश्चितता बनी हुई थी। यद्यपि दिनांक 10-05-2010 के आदेश में उनकी पेंशन स्वीकृत की गई थी, तथापि अनुपस्थिति की अवधि कथित रूप से 29-08-08 से 26-11-09 तक की गई थी। न्यायालय के समक्ष अपनी रिट याचिका दिनांक 24.04.10 में, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द करने वाले कैट के दिनांक 16.03.10 के आदेश को चुनौती देते हुए, केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि उसकी अनुपस्थिति की अवधि 29.08.08 - 09.06.09 थी। ड्यूटी से कथित अनुपस्थिति की उक्त दोनों अवधियां कैट के समक्ष दिनांक 06-07-09 के अपने शपथ-पत्र में सरकार के इस कथन के विरोधाभासी हैं कि उन्होंने दिनांक 06-04-2009 को कार्यभार ग्रहण किया था। सुश्री भाटिया द्वारा यह तर्क दिया गया था कि उन्होंने अपने कार्यालय में काम करने के लिए कानून में

उपलब्ध सभी उपचारों का उपयोग किया - और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मांग की - कि उन्हें लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने रोकने के लिए अपनाये जा रहे गलत तरीकों को रोकने के लिए कार्रवाई की जाए । विभाग के इस आरोप का विरोध करते हुए कि वह 29.08.08 से 26.11.08 तक इयूटी से अनुपस्थित थी, यह तर्क दिया गया कि सरकार ने केन्द्रीय सिविल सेवा (सीसीए) नियम 1964 के तहत आवेदक के खिलाफ कार्रवाई की होगी। केंद्र सरकार ने मू.आ. संख्या 1665/10 और 1967/10 में कैट के दिनांक 28.04.2011 के आदेश के बाद भी इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की, जिसमें निर्देश दिया गया था कि (i) या तो उसकी कथित अनुपस्थिति की अवधि को नियमित किया जाए या (ii) उसे एक निश्चित आरोप पत्र जारी करना चाहिए और कानून के अनुसार उसकी अनुपस्थिति की अवधि तय करनी चाहिए - यदि यह माना जाता है कि वह वास्तव में अनधिकृत रूप से कर्तव्य से अनुपस्थित थी। जांच करने में केंद्र सरकार की अनिच्छा उल्लेखनीय थी क्योंकि अन्यथा उसने कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत विभिन्न पुलिस स्टेशनों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंत में यह तर्क दिया गया कि पेंशन नियमों के नियम 9 में अपवादस्वरूप मामलों में, अर्थात् जहां गंभीर आरोप हों, सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्त लोक सेवकों के कदाचार के आरोपों की जांच का अधिकार दिया गया है। सुश्री भाटिया ने इस बात पर जोर दिया कि "गंभीर" कदाचार शब्द की व्याख्या ऐसे दुर्लभ मामलों में की जानी

चाहिए जहां लोक सेवक का आचरण निंदनीय हो और नैतिक अधमता शामिल हो। उन्होंने कहा कि यह संभवतः वर्तमान जैसे मामलों तक सीमित नहीं हो सकता है, जहां केंद्र सरकार सेवा की अवधि के दौरान कथित कदाचार से अवगत है, पूर्ण वेतन और भत्ते देती है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश जारी करती है और उसके बाद जांच करने के लिए कुछ भी नहीं करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस मामले में केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा है कि अगर वह छुट्टी के लिए आवेदन करती हैं तो कोई जांच नहीं की जाएगी, जो स्वाभाविक रूप से दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस तरह का आचरण सरकारी कर्मचारी की कार्रवाई को "गंभीर कदाचार" होने की संभावना को खारिज करता है। उन्होंने कहा कि इस तरह का आचरण लोक सेवक की कार्रवाई के "गंभीर कदाचार" होने की संभावना को खारिज करता है।

विश्लेषण और निष्कर्ष

24. जैसा कि स्पष्ट है, वर्तमान कार्यवाही का दायरा न्यायाधिकरण के आदेश की शुद्धता के संबंध में है, जो केंद्र सरकार को सुश्री भाटिया के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने से रोकता है, और सभी सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभों को जारी करने का निर्देश देता है।

25. इस आदेश के पिछले भाग में तथ्यात्मक विवरण से पता चलता है कि सुश्री भाटिया ने नवंबर 2007 में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। वर्तमान रिट याचिका में सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार ने इस न्यायालय

द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में, दो जांच रिपोर्टों और कुछ अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की थीं। उन्हें न्यायालय में खोला गया और बाद में, उन रिपोर्टों और दस्तावेजों की प्रतियां न्यायालय को उस पर विचार के लिए उपलब्ध कराई गईं।

26. पहली समिति (शशि प्रभा समिति) में शशि प्रभा, (अध्यक्ष), सुश्री अनीता मेनन, मैसर्स पी.सी. सुश्री निर्मला मल्ला; ए.के. चतुर्वेदी; सुश्री अंजलि पांडे और सुश्री तारा कार्था। इस समिति के निष्कर्ष अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार हैं:

"यौन उत्पीड़न के संबंध में श्री सुनील उके के खिलाफ सुश्री निशा प्रिया भाटिया की शिकायत का समर्थन करने के लिए सबूतों का अभाव है। इसके अलावा, 24.12.2007 (अनुलग्नक-ज) के अपने पत्र में सुश्री भाटिया ने स्वयं श्री सुनील उके के खिलाफ शिकायत वापस ले ली है। विभाग ने 30 अगस्त 2007 को श्री उके को उनके मूल कैडर में वापस भेज दिया है। हालांकि सुश्री भाटिया द्वारा श्री उके के खिलाफ उत्पीड़न के बारे में की गई शिकायत को किसी भी सबूत के अभाव में पुष्ट नहीं किया जा सका, लेकिन सीडी (अनुलग्नक-थ -1 से थ-8) में छह गवाहों के कथन/बयान दोनों अधिकारियों के बीच तनावपूर्ण संबंधों का संकेत देते हैं। श्री सुनील उके द्वारा समिति को दी गई अपनी रिपोर्ट (अनुलग्नक-ब में संलग्न प्रतिलिपि) में सुश्री भाटिया के खिलाफ शुरू से ही पक्षपातपूर्ण रवैया दर्शाया गया है, जो कि सीआईएस के निदेशक के रूप में उनकी पिछली पोस्टिंग और अन्य अधिकारियों से सुश्री भाटिया के बारे में सुनी-सुनाई बातों पर आधारित है। उनका यह कथन कि सुश्री

भाटिया की प्रतिष्ठा विभाग में सभी को अच्छी तरह से पता है” एक महिला कनिष्ठ सहकर्मी के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैये को दर्शाता है। उनका बयान कि सुश्री भाटिया की प्रतिष्ठा विभाग में सभी को अच्छी तरह से पता है। एक महिला जूनियर सहयोगी के प्रति पूर्वाग्रही रवैये का खुलासा करता है।

2. हालांकि श्री सुनील उके के खिलाफ सुश्री भाटिया की यौन उत्पीड़न की शिकायत को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, लेकिन समिति के समक्ष श्री सुनील उके की अपनी प्रस्तुति सहित परिस्थितिजन्य साक्ष्य एक कनिष्ठ महिला सहकर्मी के प्रति श्री उके के भेदभावपूर्ण रवैये की ओर इशारा करते हैं जो स्वयं इस मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित लैंगिक समानता के अधिकार की भावना का उल्लंघन करता है।

3. सुश्री भाटिया द्वारा आत्महत्या की धमकी, अन्य लोगों द्वारा उन्हें दी गई धमकियों के आरोप तथा बाद के अवसरों पर उनके व्यवहार (अनुलग्नक-ग) से ऐसा प्रतीत होता है कि वह मानसिक रूप से परेशान हैं। ऐसे में काउंसलिंग से उन्हें लाभ हो सकता है।

4. समिति ने सुश्री निशा प्रिया भाटिया द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर विचार करने की कोशिश की। हालांकि समिति ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के “सबूत” प्रदान करने में कठिनाइयों को स्वीकार किया। यह पाया गया कि सुश्री निशा प्रिया भाटिया ने समिति के समक्ष उपस्थित होने से इनकार कर दिया, जबकि उन्हें सात बार नोटिस भेजा गया था,

जिससे समिति इन मुद्दों का कोई सार्थक मूल्यांकन करने में असमर्थ रही।

27. केंद्र सरकार ने सुश्री भाटिया द्वारा लगाए गए समान आरोपों की जांच के लिए स्पष्ट रूप से एक और समिति का गठन किया। इस समिति को श्री अशोक चतुर्वेदी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करने का कार्य सौंपा गया था। समिति में बहुत वरिष्ठ उच्च रैंकिंग वाले सेवानिवृत्त नौकरशाह शामिल थे, और इसकी अध्यक्षता सुश्री राठी विनय झा, (आईएएस सेवानिवृत्त) ने की थी। रिपोर्ट में सुश्री भाटिया के आरोपों का समर्थन करने के लिए सबूत नहीं मिले। रिपोर्ट में सुश्री भाटिया के आरोपों का समर्थन करने वाले कोई सबूत नहीं मिले। हालाँकि, 23-01-2009 की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियाँ नुकसानदायक हैं। वे नीचे उद्धृत हैं:

XXXX

XXXX

XXXX

(ख) आचरण और अनुशासन से संबंधित सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों के नियमों/विनियमों में यौन उत्पीड़न को प्रतिबंधित करने वाले नियम/विनियम शामिल होने चाहिए और ऐसे नियमों में अपराधी के खिलाफ उचित दंड का प्रावधान होना चाहिए।

(ग) जहां तक निजी नियोक्ताओं का संबंध है, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अंतर्गत स्थायी आदेशों में उपर्युक्त प्रतिबंधों को शामिल करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

(घ) कार्य अवकाश, स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में उपयुक्त कार्य परिस्थितियां प्रदान की जानी चाहिए ताकि यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य स्थलों पर महिलाओं के प्रति कोई प्रतिकूल वातावरण न हो और किसी भी कर्मचारी महिला के पास यह मानने के लिए उचित आधार नहीं होना चाहिए कि वह अपने रोजगार के संबंध में वंचित है।

इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए श्री अशोक चतुर्वेदी को सुश्री निशा प्रिया भाटिया की शिकायत को गंभीरता से लेना चाहिए था और औपचारिक रूप से जांच करनी चाहिए थी। यह टिप्पणी ऐसी शिकायतों और स्थितियों के प्रति उनके उदासीन रवैये को दर्शाती है।

(ii) अगस्त, 2007 के आरंभ में प्राप्त उक्त शिकायत को तत्काल विभाग में यौन उत्पीड़न समिति को नहीं भेजा गया था। समिति को भेजने में दिसम्बर, 2007 तक विलंब हुआ था।

(iii) विशाखा दिशा-निर्देशों के अनुसार यौन उत्पीड़न पर विभागीय समिति का गठन भी ठीक से नहीं किया गया था। इस आवश्यकता के अनुसार, शिकायत समिति में किसी एनजीओ या अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में एक तीसरा पक्ष होना चाहिए था जो यौन उत्पीड़न के मुद्दे से परिचित हो, जबकि यौन उत्पीड़न समिति का पुनर्गठन 01.11.2007 को किया गया था। सुश्री तारा कार्था, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को अप्रैल 2008 में ही इस समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। यह स्पष्ट नहीं है कि सुश्री तारा कार्था किस तरह से एक गैर सरकारी संगठन या यौन उत्पीड़न के मुद्दे से परिचित किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए योग्य थीं, इसलिए इस स्तर पर भी, यह विशाखा दिशानिर्देशों के अनुसार गठित समिति नहीं थी।

(iv) शिकायत समिति ने कहा कि विभागीय समिति से कई नोटिस मिलने के बावजूद शिकायत समिति ने नोट किया। सुश्री निशा प्रिया भाटिया निम्नलिखित आधारों का हवाला देते हुए उनके समक्ष उपस्थित नहीं हुईं:

- विशाखा दिशा-निर्देशों के अनुसार विभागीय समिति के गठन की आवश्यकता ।

- जो यौन उत्पीड़न की उसकी शिकायत श्री अशोक चतुर्वेदी, सचिव (आर)

भी उसके खिलाफ है

- जो शिकायत समिति के अध्यक्ष इतने वरिष्ठ नहीं हैं कि श्री सुनील उके संयुक्त सचिव श्री अशोक चतुर्वेदी और सचिव (आर), के विरुद्ध आरोपों की जांच कर सकें

अप्रैल 2008 में, उन्होंने यह संकेत देने के लिए नोट भेजे कि चूंकि कैबिनेट सचिवालय इस मामले की जांच कर रहा था, इसलिए वह इस कार्रवाई से संतुष्ट थीं।

(v) शिकायत समिति ने यह भी अवलोकन किया कि यौन उत्पीड़न संबंधी विभागीय समिति को सुश्री निशा प्रिया भाटिया की शिकायत को उनके पास भेजने में हुई देरी पर सवाल उठाना चाहिए था।

उन्होंने कहा कि उन्हें शिकायत के बारे में तब तक पता नहीं था जब तक कि यह उनकी अध्यक्षता वाली समिति को नहीं भेजा गया। हालांकि, समिति के एक सदस्य के अनुसार, कार्यालय में सभी को इस घटना के बारे में पता था।

(vi) शिकायत समिति ने यह भी माना कि रॉ के लिए यह आवश्यक था कि वह सुश्री निशा प्रिया भाटिया द्वारा श्री सुनील उके के विरुद्ध यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करे, जबकि वह अभी भी विभाग में थे। श्री अशोक चतुर्वेदी का यह वक्तव्य कि श्री उके को उनके मूल विभाग में वापस भेजना सुश्री निशा प्रिया भाटिया के यौन उत्पीड़न के आरोपों की सत्यता की जांच के लिए औपचारिक रूप से कोई जांच किए जाने से पहले ही दंडात्मक कार्रवाई के रूप में था, ऐसे मामलों की जांच में उचित औपचारिक प्रक्रिया की मांग करने वाले विशाखा दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना दर्शाता है। यदि औपचारिक जांच के बाद श्री उके को दंडित करने की आवश्यकता हो तो किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रत्यावर्तन को किसी भी तरह से दंडात्मक कार्रवाई के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। यदि श्री अशोक चतुर्वेदी ने माना कि यह स्थानांतरण/प्रत्यावर्तन दंडात्मक कार्रवाई थी, तो इसका तात्पर्य यह है कि सुश्री निशा प्रिया भाटिया द्वारा लगाया गया यौन उत्पीड़न का आरोप सही/स्थापित था।

मई, 2008 में प्रस्तुत यौन उत्पीड़न संबंधी विभागीय समिति की रिपोर्ट की जांच से यह सिद्ध हुआ कि सुश्री निशा प्रिया भाटिया द्वारा की गई शिकायत पर समय पर ध्यान नहीं दिया गया अथवा उचित जांच और निवारण नहीं किया गया।

फाइल पर श्री अशोक चतुर्वेदी द्वारा लिखित टिप्पणियाँ शिकायत पर तत्काल ध्यान सुनिश्चित करने के लिए उनकी चिंता या सम्मान की कमी को दर्शाती हैं। यह श्री अशोक चतुर्वेदी को विशाखा दिशा-निर्देशों में आवश्यकताओं के बारे में ज्ञान की कमी को भी दर्शाता है।

इसके अलावा जब शिकायत यौन उत्पीड़न पर विभागीय समिति को भेजी गई थी, तब भी सचिव (आर) ने विशाखा दिशानिर्देशों में आवश्यक समिति के गठन पर ध्यान नहीं दिया।

इसलिए यह कृत्य विशाखा दिशा-निर्देशों का घोर उल्लंघन था।“

28. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का तर्क है - हम सही मानते हैं - कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित रिपोर्ट पिछली अवधि से संबंधित है; यहां केंद्र सरकार का तर्क इस तथ्य पर है कि अनधिकृत अनुपस्थिति का कदाचार बाद की अवधि यानी 29.08.2008 से 26.11.2009 तक का है। जबकि इस तर्क में निर्विवाद योग्यता है, न्यायालय एक ही समय में उन तथ्यों की प्रासंगिकता को पूरी तरह से कम नहीं करेगी। जैसा कि प्रायः कहा जाता है, आने वाली घटनाओं ने अपनी छाया डाली। इस मामले में, समिति की टिप्पणियां - विशेष रूप से राठी विनय झा समिति द्वारा जनवरी, 2009 के रिपोर्ट में की गई टिप्पणी केंद्र सरकार के लिए हानिकारक हैं, जो स्पष्ट तौर पर विशाखा दिशानिर्देशों (विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में अनिवार्य) द्वारा अनिवार्य शिकायत समिति के निवारण और स्थापना के लिए समय पर और पर्याप्त कार्रवाई नहीं करने के लिए दोषी है। [1997(7) एससीसी 323]।

29. विशाखा में दिशानिर्देश लागू करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कार्यस्थल सुरक्षित प्रदान किया गया था, और महिला कर्मचारियों को

आश्वस्त करना था कि भविष्य में इसी तरह के व्यवहार की स्थिति में, नियोक्ता त्वरित और गंभीर कार्रवाई करेगा। उस अर्थ में, कार्रवाई करने की आवश्यकता केवल घटना, या किसी मामले के तथ्यों के लिए व्यक्तिपरक नहीं है, यह एक व्यापक सामाजिक उद्देश्य का अनुपालन करना और उसे पूरा करना है। यह नियोक्ता की उपचारात्मक कार्रवाई करने की इच्छा को भी दर्शाता है जो महिला कर्मचारियों और अधिकारियों को आश्वस्त करेगा कि उनका कार्यस्थल उत्पीड़न और भेदभाव से सुरक्षित है। वही *मेधा कोतवाल लेले बनाम भारत संघ* मामले में सर्वोच्च न्यायालय के बाद के निर्णय ने विशाखा फैसले में एक और नया आयाम जोड़ा, इसके द्वारा जारी किये गये निर्देश दूरगामी हैं। इसे यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"16. हमने ऊपर जो चर्चा किया है, उसमें हमारा विचार है कि विशाखा में दिशानिर्देश प्रतीकात्मक नहीं रहने चाहिए और इस विषय पर विधायी अधिनियमन होने तक निम्नलिखित आगे के निर्देश आवश्यक हैं।

(i) जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक अपने संबंधित सिविल सेवा आचरण नियमों (इन नियमों को चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) में पर्याप्त और उचित संशोधन नहीं किए हैं, वे आज से दो महीने के भीतर ऐसा करेंगे, बशर्ते कि शिकायत समिति की रिपोर्ट को ऐसे सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई में जांच रिपोर्ट माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी शिकायत समिति की रिपोर्ट/निष्कर्ष आदि को दोषी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच में निष्कर्ष के रूप में मानेंगे और तदनुसार ऐसी रिपोर्ट पर कार्रवाई करेंगे। शिकायत समिति के निष्कर्षों और रिपोर्ट को केवल प्रारंभिक

जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई की ओर ले जाने वाली जांच के रूप में नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे दोषी के कदाचार की जांच में निष्कर्ष/रिपोर्ट के रूप में माना जाएगा।।

(ii) जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) नियमों में संशोधन नहीं किए हैं, वे अब दो महीने के भीतर उसी तर्ज पर संशोधन करेंगे, जैसा कि ऊपर खंड (i) में उल्लेख किया गया है।

(iii) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पर्याप्त संख्या में शिकायत समितियां बनाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे तालुका स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर कार्य कर रही हैं। जिन राज्यों और आर्या केन्द्र शासित प्रदेशों ने पूरे राज्य के लिए केवल एक समिति का गठन किया है, उन्हें अब दो महीने के भीतर पर्याप्त संख्या में शिकायत समितियां गठित करनी होंगी। ऐसी प्रत्येक शिकायत समिति की अध्यक्षता एक महिला द्वारा की जाएगी और जहां तक संभव हो ऐसी समितियों में एक स्वतंत्र सदस्य को संबद्ध किया जाएगा।

(iv) राज्य के पदाधिकारी और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / संगठन / निकाय / संस्थान आदि विशाखा दिशानिर्देशों के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तंत्र स्थापित करेंगे और आगे यह भी प्रावधान करेंगे कि यदि कथित उत्पीड़क दोषी पाया जाता है, तो शिकायतकर्ता-पीड़ित को ऐसे उत्पीड़क के अधीन काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जायेगा और जहां उचित और संभव हो तो कथित उत्पीड़क को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इसके अलावा यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि गवाहों और शिकायतकर्ताओं को परेशान करने और डराने-धमकाने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(v) भारतीय बार काउंसिल यह सुनिश्चित करेगी कि देश के सभी बार एसोसिएशन और राज्य बार काउंसिल के साथ पंजीकृत व्यक्ति विशाखा दिशानिर्देशों का पालन करें। इसी प्रकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, वास्तुकला परिषद, चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, कंपनी सचिव संस्थान और अन्य सांविधिक संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि संगठन, निकाय, संघ, संस्थाएं और उनके साथ पंजीकृत संबंधित व्यक्ति द्वारा निर्धारित विशाखा दिशानिर्देशों का पालन करें। इसे पूरा करने के लिए, सभी सांविधिक निकायों जैसे भारत का बार काउंसिल, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, वास्तुकला परिषद, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज द्वारा आज से दो महीने के भीतर आवश्यक निर्देश परिपत्र जारी किए जाएंगे। उपर्युक्त किसी भी स्थान पर यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त होने पर विशाखा दिशा-निर्देशों और वर्तमान आदेश में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार सांविधिक निकायों द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी।

17. हमारा मानना है कि इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार यदि विशाखा और उपरोक्त निर्देशों का कोई गैर-अनुपालन हुआ या पालन नहीं किया गया है तो पीड़ित व्यक्तियों के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों से संपर्क करने का विकल्प खुला रहेगा। ऐसे राज्य का उच्च न्यायालय इस संबंध में की गई शिकायतों पर प्रभावी ढंग से विचार करने की बेहतर स्थिति में होगा।”

इससे पहले, मेधा कोतवाल लेले में कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किए थे; इन्हें अंतिम निर्णय में उद्धृत किया गया था:

"26.4.2004 को, भारत का महान्यायावादी और राज्यों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्देश दिया:

"शिकायत समिति जैसा कि विशाखा के मामले में अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिकल्पित है, को केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 (इसके बाद सीसीएस नियम कहा गया है) के उद्देश्यों के लिए एक जांच प्राधिकरण माना जाएगा और शिकायत समिति की रिपोर्ट केन्द्रीय सिविल सेवा नियमों के तहत एक जांच रिपोर्ट माना जाएगा। इसके बाद अनुशासनात्मक प्राधिकारी नियमों के अनुसार रिपोर्ट पर कार्रवाई करेगा।

30. यह न्यायालय बार-बार उपरोक्त पहलू पर जोर देता है और रेखांकित करता है क्योंकि, हालांकि यह तय करने के लिए सीधे प्रासंगिक नहीं है कि क्या कैट के आक्षेपित निर्देश उचित थे, उन्होंने एक प्रासंगिक पृष्ठभूमि प्रदान की जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। संदर्भ यह था कि सुश्री भाटिया को "हठी" माना जाता था और एक सहयोगी के साथ उनके संबंध तनावपूर्ण थे (इसे हल्के ढंग से रखने के लिए) और उनके बारे में उनके विचार अपमानजनक थे - शशि प्रभा समिति द्वारा तैयार किया गया निष्कर्ष यही था। इसी तरह, राठी विनय झा समिति के निष्कर्ष भी समयबद्ध प्रतिक्रिया के संदर्भ में केंद्र सरकार की अपर्याप्तता को दर्शाते हैं। बाद की समिति ने यहां तक कहा कि श्री उके का स्थानांतरण सुश्री भाटिया के आरोपों की पुष्टि है।

31. ये तथ्य और परिस्थितियां, जब सुश्री भाटिया एक कटु वातावरण में थीं जो कि उनकी यह तैनाती एक आदेश के अधीन हुई थी जिसमें 08.11.07 को निदेशक (प्रशिक्षण) के रूप में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। केन्द्र सरकार द्वारा इस बात से इंकार नहीं किया गया है कि एक अन्य अधिकारी

उक्त समय का निदेशक प्रारंभ में निदेशक (जनसंपर्क अधिकारी) मुख्यालय के रूप में तैनात किया गया था। एक सप्ताह बाद दिनांक 16-11-2007 के एक अन्य आदेश द्वारा उस स्थानांतरण आदेश को रद्द कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि निदेशक (प्रशिक्षण) के एक स्वीकृत पद पर दो अधिकारियों की तैनाती की गई। सुश्री भाटिया का यह आरोप कि चूंकि श्री महापात्र पीठासीन निदेशक (प्रशिक्षण) थे, इसलिए उन पर कोई कार्य प्रभार नहीं था। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि राँ में निदेशक (प्रशिक्षण) का केवल एक स्वीकृत पद मौजूद है। इसे लेखा अधिकारी (बी एंड एफ) के दिनांक 08.04.08 के एक नोट द्वारा स्थापित किया गया है। सुश्री भाटिया ने यह भी आरोप लगाया कि एक संस्थान के प्रमुख के रूप में, उन्हें काम करने के लिए शौचालय के बगल में एक जर्जर कक्ष दिया गया था। इन परिस्थितियों में वह छुट्टी पर चली गईं और फिर शिकायत की और निदेशक (प्रशिक्षण) के पद के अपने प्रभार का दावा करने के लिए पीएमओ में प्रतिनिधित्व किया। ये तथ्य अनधिकृत अनुपस्थिति के कथित कदाचार में परिणत होते हैं; हालांकि, वे कार्यस्थल पर उत्पीड़न के उनके आरोपों से भी जुड़े हुए हैं। ये तथ्य अनधिकृत अनुपस्थिति के कथित कदाचार में परिणत होते हैं; हालांकि वे कार्यस्थल पर उत्पीड़न के उनके आरोपों से भी जुड़े हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि उत्पीड़न का कृत्य एक घटना हो सकती है, या कई घटनाओं की एक श्रृंखला हो सकती है; उचित तरीके से जवाब न देना (जैसा कि झा समिति ने

टिप्पणी की है) भी उत्पीड़न माना जा सकता है। इस प्रकार, नवंबर 2007 के बाद की घटनाएं सुश्री भाटिया के खिलाफ लगाए गए कदाचार के आरोपों के साथ जुड़ती हुई एक जीवंत कड़ी हैं और इसलिए, इनकी भी कुछ प्रासंगिकता है।

31. यह रिकॉर्ड की बात है कि सुश्री भाटिया ने 2008 में ही (मू.आ.संख्या 2687/08 के माध्यम से) नवंबर (2008) में कैट से संपर्क किया और दावा किया कि उन्हें उनके रैंक और स्थिति के अनुरूप पोस्टिंग दी जानी चाहिए। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके कार्यालय में जबरन छेड़छाड़ की गई है, साथ ही गंभीर आरोप भी लगाए थे। केंद्र सरकार के हलफनामे में आरोपों का खंडन करते हुए कहा गया है कि: *"आवेदक अपनी अलमारी में [याचिकाकर्ता संगठन के अधिकारियों द्वारा] जो कुछ भी पाया गया था उसे एकत्र कर सकता है। जो सुरक्षित पड़ा है। आवेदक से संबंधित कुछ भी सीलबंद हिरासत में नहीं रखा गया है।"* कार्यवाही में 15.05.2009 कैट ने आदेश जारी करते हुए केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह सुश्री भाटिया को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दे तथा स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उनके आग्रह को अनदेखा कर दिया जाए। इसी कार्यवाही में, एक विविध आवेदन (मू.आ.संख्या 2687/08 में वि.आ. संख्या 1089/2009) का निपटारा करते हुए, कैट ने 26.11.09 को निर्देश दिया कि:

"विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि प्रत्यर्थी (याचिकाकर्ता संगठन के अधिकारी) छह महीने के बाद

आवेदक को कार्यकारी केंद्र में वापस भेजने पर विचार करेंगे जब गुस्सा ठंडा हो गया हो।

08-12-2009 को सुश्री भाटिया को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का आदेश जारी किया गया था। केन्द्र सरकार ने उनकी अंतिम बकाया राशि का भुगतान नहीं किया, बल्कि उन्हें अनंतिम पेंशन देने की मांग की गई। इस कदम के खिलाफ कैंट को दिए गए उनके आवेदन (मू.आ. 1665/2010 और 1967/2010) और केंद्र सरकार का यह रुख कि 29.08.2008 और 26.11.2009 के बीच वह अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थीं, का निपटारा कर दिया गया और केंद्र को निर्देश दिया गया कि वह पहले अपने रिकॉर्ड की जांच करके यह पता लगाए कि क्या किसी अवधि या अवधि को इयूटी पर माना जा सकता है और फिर तथ्यात्मक जांच करे। केन्द्र सरकार ने कैंट द्वारा आबंटित समय के साथ अपना कार्य पूरा नहीं किया; इसने सुश्री भाटिया को एक और आवेदन मू.आ. दायर करने के लिए प्रेरित किया इस कार्यवाही में, केंद्र सरकार ने निर्देशों के लिए एक विविध आवेदन के जवाब में एक हलफनामा दायर किया। उक्त हलफनामे में महत्वपूर्ण रूप से यह कहा गया था कि:

"उसकी अनुपस्थिति की कुल अवधि - 29.08.2008 से 26.11.2009 है। संयुक्त सचिव द्वारा की गई आंतरिक जांच के अनुसार, उपस्थिति रजिस्टर की प्रति पर विचार करने के बाद, 07.04.2009 से 09.06.2009 (63 दिन) की अवधि को "इयूटी पर" माना जा सकता है, जिससे उसे संदेह

का लाभ मिलता है। जहां तक 29-08-2008 से 05-04-2009 और 10-06-2009 से 26-11-2009 (390 दिन) तक की शेष अवधि को निम्नानुसार माना जा सकता है "चाइल्ड केयर लीव"/"अर्जित अवकाश।"

7. यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि आवेदक (सुश्री निशा प्रिया भाटिया) को पूरी अवधि के लिए पूरे वेतन का भुगतान किया गया है अर्थात् 29.08.2008 से 26.11.2009 तक अन्य सभी लाभों के साथ, जिसकी वह हकदार थी।"

यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि श्री विनोद कुमार का शपथ-पत्र, उप सचिव, सुश्री भाटिया के आवेदन के जवाब में (मू.आ.संख्या 2687/08 में) ने स्वीकार किया कि वह 06-04-2009 को अपना दायित्व ग्रहण की थीं:

"पैरा 3 - यह स्वीकार किया जाता है कि आवेदक ने 06.04.09 को कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया था। यह भी दोहराया जाता है कि 29.08.08 से अनुपस्थित रहने के बावजूद आवेदक का दूसरा पोस्टिंग आदेश 27.11.08 को जारी किया गया था और उसे कभी भी कार्यालय में उपस्थित होने से नहीं रोका गया था। 29.08.08 से ड्यूटी से उसकी अनुपस्थिति उसकी अपनी इच्छा से थी। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उसकी पोस्टिंग का आदेश आधा टाइप किया हुआ और आधा कम्प्यूटरीकृत है या नहीं, यह तब तक महत्वहीन है जब तक कि उस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों।"

महत्वपूर्ण रूप से, इस हलफनामे में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि सुश्री भाटिया की अनुपस्थिति अनधिकृत थी।

32. पेंशन नियम (1972) के प्रासंगिक प्रावधान नियम 8 (5) के स्पष्टीकरण (ख) और नियम 9 हैं। पूर्व (नियम 8 (5) के स्पष्टीकरण (ख) इस प्रकार है:

"(ख) 'गम्भीर कदाचार' में किसी गुप्त सरकारी कोड या पासवर्ड या किसी रेखाचित्र, योजना, मॉडल, लेख, नोट, दस्तावेज या सूचना, जैसा कि सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 (1923 का 19) की धारा 5 में उल्लिखित है (जो सरकार के अधीन पद पर रहते हुए प्राप्त की गई हो) संचार या प्रकटीकरण शामिल है, जिससे आम जनता के हितों या राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

नियम 9, जहां तक यह प्रासंगिक है, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"9. पेंशन रोकने या निष्कासन का राष्ट्रपति का अधिकार

'[(1) राष्ट्रपति अपने पास पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों को पूर्ण या आंशिक रूप से रोकने या पूर्ण या आंशिक रूप से पेंशन को वापस लेने का, चाहे स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए, और सरकार को हुई किसी भी आर्थिक हानि के संपूर्ण या भाग की पेंशन या ग्रेच्युटी से वसूली का आदेश देने का अधिकार सुरक्षित है, यदि किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में, पेंशनभोगी सेवा की अवधि के दौरान गंभीर कदाचार या लापरवाही का दोषी पाया जाता है, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नियोजन पर प्रदान की गई सेवा भी शामिल है:

(2)..... (ख) विभागीय कार्यवाही, यदि सरकारी सेवक के सेवा में रहते हुए शुरू नहीं की गई हो, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति से पहले, या उसके पुनः नियोजन के दौरान, -

(i) राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना शुरू नहीं किया जाएगा, (ii) किसी ऐसी घटना के संबंध में नहीं होगा जो ऐसी संस्था से चार वर्ष से अधिक पहले हुई थी, और

(iii) ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे स्थान पर संचालित किया जाएगा जो राष्ट्रपति निर्देश दे और विभागीय कार्यवाहियों के लिए लागू प्रक्रिया के अनुसार जिसमें सरकारी सेवक के संबंध में उसकी सेवा के दौरान सेवा से बर्खास्तगी का आदेश दिया जा सकता है।

33. यह एक विधिगत मामला है कि आम रोजगार किस दशा में उत्पन्न होता है (यानी अनुबंध के बजाय कानून कार्यकाल और रोजगार की शर्तों को नियंत्रित करता है। सं. रोशनलाल टंडन बनाम भारत संघ एआईआर 1968 एससी)। समान रूप से, पेंशन न तो इनाम है और न ही उदारता है, बल्कि स्थगित वेतन है, जिसे सार्वजनिक कर्मचारी को कानून सिवाय किसी कानूनी प्रक्रिया के वंचित नहीं किया जा सकता है (डी.एस. नकारा बनाम भारत संघ 1983 (2) एससीआर 165)। इस सिद्धांत के अनुरूप ही केंद्र सरकार ने पेंशन नियमावली का नियम 9 बनाया है। यह एक ऐसी स्थिति की कल्पना करता है जहां पेंशन प्राप्त करने वाले एक सरकारी कर्मचारी को उस पेंशन के एक हिस्से से वंचित किया जा सकता है, बशर्ते कि एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए और पूर्व शर्तों को पूरा किया जाए। ये न केवल प्रक्रियाएं हैं, बल्कि सुरक्षा उपाय भी हैं। एक सेवारत सार्वजनिक कर्मचारी के विपरीत, जिसे हर तरह की

चूक, कदाचार या लापरवाही, (छोटी या बड़ी) के लिए दोषी ठहराया जा सकता है और दंड की एक पूरी श्रृंखला के साथ गुजरा जा सकता है, जिसमें सबसे गंभीर है सेवा से बर्खास्तगी, एक सेवानिवृत्त सार्वजनिक कर्मचारी की पेंशन से वंचित किया जा सकता है केवल अगर वह (या वह) गंभीर कदाचार या लापरवाही का दोषी पाया जाता है। "गंभीर" शब्द का प्रयोग गंभीरता की एक डिग्री को बढ़ा देता है। इसके अलावा, यह जांच पूरी होनी चाहिए और सेवानिवृत्त लोक सेवक को उसकी सेवानिवृत्ति के चार साल के भीतर इस तरह के गंभीर कदाचार का दोषी पाया जाना चाहिए। "प्रतिस्थापन" शब्द विभागीय जांच का प्रस्ताव करते हुए आरोप पत्र जारी करने को संदर्भित करता है। डी.वी. कपूर बनाम भारत संघ एआईआर 1990 एससी 1923 में, सर्वोच्च न्यायालय को नियम 9 से निपटने का अवसर मिला; न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की।:

"यह देखा गया है कि राष्ट्रपति ने पेंशन को पूरी तरह से या आंशिक रूप से रोकने का अधिकार सुरक्षित रखा है, चाहे वह स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए हो या वह सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकार को होने वाले किसी भी आर्थिक नुकसान के पूरे या हिस्से की पेंशन से वसूल कर सकता है, बशर्ते कि न्यूनतम हो। पूर्ववर्ती शर्त यह है कि किसी भी विभागीय जांच या न्यायिक कार्यवाही में, पेंशनभोगी को मूल या पुनर्नयोजन की उसकी सेवा की अवधि के दौरान गंभीर कदाचार या लापरवाही का दोषी पाया गया हो। पूर्ववर्ती शर्त यह है कि यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि अपराधी कार्यालय में सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर कदाचार या लापरवाही का दोषी है, जैसा कि नियम 8 (5), स्पष्टीकरण (ख) में परिभाषित किया गया है, जो एक समावेशी

परिभाषा है, अर्थात् जिसके क्षेत्र का दायरा व्यापक है जो किसी दिए गए मामले में तथ्यों या परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अनगिनत स्थितियाँ उस विदग्धता के आधार पर उत्पन्न हो सकती हैं जिसके साथ कदाचार या अनियमितता की गई थी। 'गंभीर कदाचार या लापरवाही' शब्दों की संभावना और अर्थ की आगे जांच करना और किन परिस्थितियों में इस संबंध में निष्कर्ष साबित होते हैं आवश्यक नहीं है।

6. जैसा कि देखा गया है, राष्ट्रपति द्वारा शक्ति के प्रयोग को एक पूर्ववर्ती शर्त के साथ बचाव किया जाता है कि एक निष्कर्ष या तो विभागीय जांच या न्यायिक कार्यवाही में दर्ज किया जाना चाहिए कि पेंशनभोगी ने पद पर रहते हुए अपने कर्तव्य के निर्वहन में, आरोप के अधीन गंभीर कदाचार या लापरवाही की है। इस तरह के निष्कर्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पास कानून के अधिकार के बिना है कि वह या तो पूरे या आंशिक रूप से स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए सजा के उपाय के रूप में पेंशन को रोकने का जुर्माना लगाए, या कर्मचारी की पेंशन से पूरे या आंशिक रूप से न्यूनतम 60 रुपये के अधीन आर्थिक नुकसान की वसूली का आदेश दे।

7. नियमों का नियम 9 राष्ट्रपति को केवल स्थायी रूप से या एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से पेंशन को रोकने या वापस लेने या राज्य को हुई पूर्ण या आंशिक रूप से हुई आर्थिक हानि की वसूली का आदेश देने का अधिकार देता है, बशर्ते कि वह न्यूनतम हो। कर्मचारी का पेंशन का अधिकार एक वैधानिक लड़ाई है। कर्मचारी का पेंशन पाने का अधिकार एक वैधानिक लड़ाई है। इसलिए, इससे वंचित करने का उपाय तब किया जाना चाहिए जब यह गंभीर कदाचार या अनियमितता की गंभीरता के साथ सहसंबंधी या अनुरूप हो क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत आश्वासन वृद्धावस्था में दिए गए सहायता अधिकार का उल्लंघन करता है।

34. केंद्र सरकार द्वारा उसके समक्ष दिए गए हलफनामों में किए गए खुलासे के अलावा, कैट को यह मानने के लिए राजी करने वाली बात यह थी कि मामले में आगे कोई जांच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उक्त सरकार ने स्वयं ही स्थिति बदल दी थी, तथा हलफनामे में कहा था कि 63 दिनों की अवधि को "सेवा में" माना जा सकता है। फिर भी, इसके सबसे समकालीन हलफनामे (श्री विनोद कुमार का, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है) में जून, 2009 में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया कि सुश्री भाटिया लगातार अनुपस्थित रहीं। इसे 12 जून, 2009 के बाद दायर किया गया था। बाद में 2012 में दायर हलफनामे के अनुसार, सुश्री भाटिया अनधिकृत अनुपस्थिति में चूक गई थीं। दूसरा पहलू यह था कि इस बात के परस्पर विरोधी संस्करण थे कि क्या पहचान पत्र की कमी (जिसे सुश्री भाटिया द्वारा 21.08.2008 को लागू किया गया था) उनके सेवा में शामिल होने में बाधा थी। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसी कोई बाधा मौजूद नहीं है, सुश्री भाटिया ने इसका विरोध किया है। वास्तव में, पहचान पत्र फरवरी 2009 में ही जारी किया गया था। कुछ अधिकारियों और संगठन के वरिष्ठतम अधिकारी के खिलाफ लगाए गए पिछले आरोपों और सुश्री भाटिया द्वारा सामना की गई अंतर्निहित शत्रुता को ध्यान में रखते हुए, उनके बयानों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। यदि अन्य तथ्यों, जैसे कि डॉ. रे की राय (जिन्होंने सुश्री भाटिया की जांच भी नहीं की थी, लेकिन उनके मानसिक स्वास्थ्य पर टिप्पणी करने का साहस किया) जिसे कुछ

प्रचारित किया गया था और उनके खिलाफ दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उन्हें दी गई जानकारी के अनुसार) को ध्यान में रखा जाए, तो उनके साथ लगातार प्रतिकूल व्यवहार किए जाने और बाधा उत्पन्न किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

35. इस न्यायालय को सामान्य प्रस्ताव को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है कि दिए गए मामलों में "गंभीर कदाचार" या गंभीर लापरवाही में कर्तव्यों से एक लोक सेवक की अनधिकृत अनुपस्थिति, या उसके कार्यालय को सौंपे गए या संलग्न कार्यों का निर्वहन करने से इनकार करना शामिल है। हालांकि, क्या इयूटी के लिए रिपोर्ट करने के लिए हर चूक "गंभीर" कदाचार या लापरवाही है, यह रिकॉर्ड से दिखाई देने वाली परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। *डीवी कपूर का* मामला एक ऐसा उदाहरण है जहां इस तरह की निरंतर अनुपस्थिति को नियम 9 के तहत पेंशन रोकने के लिए "गंभीर" कदाचार नहीं माना गया था। वर्तमान मामले में, न तो कोई जांच शुरू की गई थी, न ही उस समय उस पर विचार किया गया था, जब प्रत्यर्थी, सुश्री भाटिया को अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश दिया गया था। जब केन्द्र सरकार ने उनकी देय राशि जारी करने में टालमटोल की और उसने उचित आदेश की मांग की, तभी इस न्यायालय द्वारा केन्द्र सरकार की 2010 की याचिका में 03-05-2010 को एक आदेश दिए जाने के बाद 10-05-2010 को एक अनंतिम पेंशन निर्धारण आदेश दिया गया (अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश को रद्द करने को चुनौती देना)। अनंतिम पेंशन निर्धारण

आदेश में कहा गया है कि यह "19.12.2009 से लेकर उसकी अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि के नियमित होने तक" की अवधि के लिए था। अनधिकृत अनुपस्थिति के बारे में आरोप केंद्र सरकार द्वारा मू.आ.1665/2010 और मू.आ.1967/2010 में लगाए गए थे। फिर भी, आरोप पत्र जारी करने या इस तरह की अनुपस्थिति को "गंभीर कदाचार" मानने का कोई परिश्रम या प्रयास नहीं किया गया। उन कार्यवाहियों के निपटान के बाद भी, सितंबर, 2011 में नया आवेदन - मू.आ. 3613/2011 दायर किए जाने तक, यह जांचने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि क्या चूक या आचरण नियम 9 के तहत जांच के योग्य था। इस संदर्भ में, केंद्र सरकार का हलफनामा, जिसमें कहा गया है कि कुछ अवधि (सुश्री भाटिया की अनुपस्थिति) को इयूटी पर माना जा सकता है, अत्यंत प्रासंगिक है। उस हलफनामे में, यह प्रस्तुत किया गया था कि:

"जहां तक 29-08-2008 से 05-04-2009 और 10-06-2009 से 26-11-2009 (390 दिन) की शेष अवधि को चाइल्ड केयर लीव /अर्जित अवकाश माना जा सकता है।"

36. केन्द्र सरकार की स्थिति वास्तव में विचित्र है। इस न्यायालय के समक्ष, यह तर्क देता है कि अनुपस्थिति की पूरी अवधि अनधिकृत है, और "गंभीर" कदाचार के बराबर है, नियम 9 जांच की आवश्यकता है। साथ ही, इसमें इस चूक को माफ करने की इच्छा भी व्यक्त की गई है, तथा इस अवधि को इस प्रकार माना गया है जैसे कि सुश्री भाटिया अवकाश पर थीं, बशर्ते कि

वह इसके लिए आवेदन करें। यह दृष्टिकोण, परस्पर विरोधी और असंगत है। लोक सेवकों के अस्वीकार्य व्यवहार की एक श्रेणी के "गंभीर" कदाचार को माफ करने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है, जिसमें धोखा और गबन के आरोप शामिल हैं जिसके कारण स्थायी रूप से या कुछ अवधि के लिए पेंशन जब्त की जा सकती है। केवल तथ्य यह है कि केंद्र सरकार यह बताने की स्थिति में है कि आचरण "क्षम्य" है और "नियमितीकरण" में सक्षम अवधि का अर्थ है कि यह मामले की समग्र परिस्थितियों के संबंध में "गंभीर कदाचार" नहीं है।

37. यह कहा गया है कि शक्ति, जिसमें भी निहित हो, एक सार्वजनिक प्राधिकरण या एजेंसी में, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए:

पीठ ने कहा, 'नियोक्ता, कॉरपोरेट या अनुच्छेद 12 के तहत नियोक्ता द्वारा बनाया गया कोई भी कानून या कार्रवाई निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत तरीके से होनी चाहिए। निष्पक्ष व्यवहार का अधिकार प्राकृतिक न्याय का एक अनिवार्य अंतर्निहित अधिकार है। निरंकुश और असंबद्ध विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग नागरिक के अधिकार पर अतिक्रमण करता है; विवेकाधिकार निहित करना कोई गलत नहीं है बशर्ते इसका प्रयोग उद्देश्यपूर्ण, विवेकपूर्ण और पूर्वाग्रह के बिना किया जाए। ..' (दिल्ली परिवहन निगम बनाम डीटीसी मजदूर कांग्रेस एआईआर 1990 एससी 101)।

प्रत्येक लोक प्राधिकरण का यह भी कर्तव्य है कि वह प्रदत्त या निहित शक्ति की सीमा के भीतर कार्य करे, उन उद्देश्यों को आगे बढ़ाए जिनके लिए ऐसी

शक्तियां सृजित की गई हैं और केवल प्रासंगिक परिस्थितियों पर, प्रमाणिक और युक्तियुक्त विचार करे। इनमें से किसी को छोड़कर, शक्ति का प्रयोग बनावटी है, जैसा कि पंजाब राज्य बनाम गुरदयाल सिंह, एआईआर 1979 एससी 319 में अभिनिर्धारित किया गया है:

" विचार, शक्ति के दायरे से बाहर या कानून से असंगत, फैसला दर्ज करते हैं या कार्रवाई को प्रेरित करते हैं, शक्ति पर दुर्भावनापूर्ण या धोखाधड़ी करते हैं, अधिग्रहण या अन्य आधिकारिक कार्य को दूषित करते हैं।"

इस मामले को रवि यशवंत भोईर बनाम जिला कलेक्टर, रायगढ़ और अन्य एआईआर 2012 एससी 1339, में और भी अधिक मजबूती से रखा गया था, निम्नानुसार है:

"37... वैधानिक द्वेष" या "विधि में द्वेष" का अर्थ है वैधानिक कारण के बिना कुछ किया गया। यह दूसरों के अधिकारों की अवहेलना करते हुए जानबूझकर किया गया कार्य है। यह एक ऐसा कार्य है जो किसी अप्रत्यक्ष या परोक्ष उद्देश्य से किया जाता है। यह बिना किसी उचित या संभावित कारण के गलत तरीके से और जानबूझकर किया गया कार्य है, और जरूरी नहीं कि यह दुर्भावना और द्वेष से किया गया कार्य हो। शक्ति के दुर्भावनापूर्ण प्रयोग का अर्थ कोई नैतिक अधमता नहीं है। इसका अर्थ है "कानून में जिस उद्देश्य के लिए यह अभिप्रेत है, उससे अलग उद्देश्यों के लिए वैधानिक शक्ति का प्रयोग करना।" इसका अर्थ है किसी अन्य के प्रति पूर्वाग्रह के लिए कानून का जानबूझकर उल्लंघन करना, दूसरों

के अधिकारों की अवहेलना करने के लिए प्राधिकारी की ओर से एक भ्रष्ट प्रवृत्ति, जहाँ इरादा उसके हानिकारक कार्यों से प्रकट होता है। अनधिकृत उद्देश्य के लिए आदेश पारित करने का मतलब है कानून में दुर्भावना उत्पन्न करता है।”

38. इन कार्यवाहियों में इस न्यायालय को उजागर की गई परिस्थितियों के पूरे परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, यानी सुश्री भाटिया द्वारा कार्यस्थल पर उनके यौन उत्पीड़न के संबंध में व्यक्त शिकायतों का पिछला वृत्त और विशाखा दिशानिर्देशों के अनुरूप किसी भी कार्रवाई की कमी के संबंध में केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ की गई कई प्रतिकूल टिप्पणियां (जो उनकी ओर से दोषी चूक का अभियोग है); सुश्री भाटिया के स्थानांतरण और उनके द्वारा और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों और प्रति-आरोपों के साथ उनका आंतरिक संबंध; (क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार द्वारा दायर किए गए शपथ पत्र जारी किए गए हैं; अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश के बाद किसी भी समय नियम 9 के तहत जांच करने के किसी भी प्रस्ताव के संबंध में इसकी अस्पष्ट निष्क्रियता या यहां तक कि लंबे समय तक आरोप पत्र जारी करने की चूक भी, यहां तक कि लंबे समय तक आरोप पत्र जारी न करने, आरोपों को माफ करने की उसकी इच्छा, बशर्ते कि सुश्री भाटिया छुट्टी के लिए आवेदन करें - इस न्यायालय को इसमें कोई संदेह नहीं है कि कैट का वह आक्षेपित आदेश, जिसमें केंद्र सरकार को सुश्री भाटिया की अनुपस्थिति की अवधि के आरोपों की कोई जांच न करने का निर्देश दिया गया था, न्यायोचित था और इसमें किसी

हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार, ऐसी अवधियों को *अनधिकृत अनुपस्थिति माने बिना और परिणामी कार्रवाई और छुट्टी* के लिए आवेदन की अपेक्षा किए बिना और अंतर राशि जारी किए बिना दिनांक 19-12-2009 से उनकी पेंशन निर्धारित करने के निदेश की पुष्टि की जाती है। सुश्री भाटिया को जो राशि का भुगतान किया जाना है, उसे 4 सप्ताह के भीतर जारी किया जाएगा। सभी परिणामी सेवांत लाभों को उसी अवधि के भीतर संशोधित किया जाएगा और उसे भुगतान किया जाएगा। ऐसी सभी राशियों पर प्रति वर्ष 9 प्रतिशत की दर से 19.12.2009 से भुगतान की तारीख से ब्याज लगेगा। रिट याचिका है उपरोक्त निर्देशों के अनुसार खारिज कर दिया गया। सभी लंबित आवेदन भी खारिज कर दिया जाए। याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी को 25,000/- रुपये की लागत का भुगतान करना होगा।

न्या. एस. रवीन्द्र भट

न्या. आर.वी. ईश्वर

21 अक्टूबर 2012

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।